# यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

**पंजीकरण संख्या–538**
**ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध**
**केन्द्रीय कार्यालय :** 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
**पत्र व्यवहार :** 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**


**परिपत्र संख्या :** 2019–22/123/2020 **दिनांक :** 30.07.2020

**सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों**
**जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु**

प्रिय साथियों,

## 9 अगस्त, 2020 को – भारत बचाओ दिवस

उपरोक्त विषय में एआईबीईए केन्द्रीय कार्यालय द्वारा परिपत्र संख्या 28/221/2020/59 दिनांक 27.7.2020 जारी किया गया है जिसका अनूदित सार सभी इकाईओं एवं सदस्यों की सूचना, संज्ञान एवं अनुपालन हेतु नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

**(मदन मोहन राय)**
**महामंत्री**

---

प्रिय साथियों,

## केन्द्रीय श्रम संगठनों का आह्वान
## 9 अगस्त, 2020 को – भारत बचाओ दिवस मनायें

मजदूर वर्ग के हितों के विरूद्ध सरकार की निरंतर आक्रामक नीति और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के निजीकरण, बिक्री और विनिवेश पर हालिया प्रतिगामी घोषणाओं के मद्देनजर, 22 मई और 3 जुलाई, 2020 के पूर्व संयुक्त कार्यक्रमों से आगे, केन्द्रीय श्रम संगठनों ने 9 अगस्त, 2020 को भारत बचाओ दिवस के रूप में मनाने के साथ शुरूआत करते हुए आगामी कार्यक्रमों का आह्वान किया है।

हम सभी जानते हैं कि मीडिया में दोहराई जा रही खबरों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी निजीकरण के लक्ष्य हैं।

इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि देशभर की हमारी सभी यूनियनें और सदस्य इन जन–विरोधी और कामगार–विरोधी नीतियों के विरोध में इन कार्यक्रमों का सक्रिय हिस्सा हों।

केन्द्रीय श्रम संगठनों ने कामगारों द्वारा जेल भरो/सत्याग्रह का कार्यक्रम तथा अन्य आंदोलनात्मक कार्यक्रम दिए हैं। पहले, 9 अगस्त को रविवार है और दूसरे एआईबीईए जेल भरो जैसे कार्यक्रम देने में सक्षम नहीं हो सकता। इसलिए हम केन्द्रीय श्रम संगठनों की इन कार्यवाहियों के समर्थन में अलग से कार्यक्रम देंगे क्योंकि हम उनके सभी मुद्दों और मांगों पर कामगार वर्ग के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़े हैं।

**हम बैज पहनने, पोस्टर लगाने, प्रदर्शनों, आभासी बैठकों, वेबिनार, सोशल मीडिया के माध्यम से अभियान**

*जारी पृष्ठ 2*

**आदि जैसे कार्यक्रम करेंगे जो वर्तमान परिस्थितियों में बैंक कर्मचारियों द्वारा संभव हैं। इस संबंध में अलग से परिपत्र जारी किया जायेगा।**

अभिवादन सहित,

आपका साथी
ह...
**सी.एच. वेंकटचलम्**
**महामंत्री**

---

**केन्द्रीय श्रम संगठनों की प्रदेश इकाईओं और क्षेत्रीय फैडरेशनों और एसोसिएशनों के लिए केन्द्रीय श्रम संगठनों का संयुक्त परिपत्र**

**22 जुलाई, 2020**

केन्द्रीय श्रम संगठनों के साथ–साथ क्षेत्रीय फैडरेशनों और एसोसिएशनों का राष्ट्रीय मंच 9 अगस्त को ''भारत बचाओ दिवस'' के रूप में मनाने के लिए कामगार वर्ग का आह्वान करता है। केन्द्रीय श्रम संगठन और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 18 अगस्त को कोयला हड़ताल दिवस पर एकजुटता कार्रवाई करेंगी।

केन्द्रीय श्रम संगठनों के संयुक्त मंच ने आंदोलन की अगली कार्यवाही की योजना बनाने के लिए क्षेत्रीय फैडरेशनों और एसोसिएशनों के साथ 8 जुलाई और फिर 18 जुलाई को बैठक की। बैठक ने नोट किया कि केन्द्रीय श्रम संगठनों और क्षेत्रीय फैडरेशनों तथा एसोसिएशनों के ध्वज तले कामगार वर्ग ने 3 जुलाई 2020 को देशव्यापी विरोध दिवस मनाया, जो सरकार की कामगार–विरोधी, किसान–विरोधी, जन–विरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियों के असहयोग एवं अवज्ञा के संयुक्त संघर्ष के रूप में सभी कार्यस्थलों और केन्द्रों पर, देशभर में एक बड़ी सफलता रहा। कार्रवाई कार्यक्रम राज्यों में कार्यस्थलों, यूनियन कार्यालयों, सड़कों और गलियों पर लगभग एक लाख स्थानों पर आयोजित किए गए जिसमें जुलूस, साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियां, जनसभायें शामिल थीं।

केन्द्रीय श्रम संगठनों, स्वतंत्र क्षेत्रीय फैडरेशनों और एसोसिएशनों के संयुक्त मंच ने कोयला कामगारों को बधाई दी जिन्होंने कोयले के उत्पादन और प्रेषण को पूर्णतया रोकते हुए कोल इंडिया और एससीसीएल के अधीन कोयला खदानों और प्रतिष्ठानों को लाने के लिए 2–3–4 जुलाई 2020 को 3 दिनों तक सफलतापूर्वक हड़ताल आयोजित की। इस हड़ताल का आह्वान निजी क्षेत्र सहित विदेशी संस्थाओं द्वारा कोयले के अनियमित वाणिज्यिक खनन और व्यापार के माध्यम से कोयला क्षेत्र का पूरी तरह से निजीकरण करने के सरकार के फैसले का विरोध करने के लिए किया गया था जिससे राष्ट्रीय हितों और आत्म–निर्भरता की अत्यधिक हानि होती है। कोयला यूनियनों ने एक बार फिर 18 अगस्त 2020 को हड़ताल पर जाने का फैसला किया है – निजी वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला ब्लॉकों के आवंटन हेतु बोली लगाने का आखिरी दिन।

बैठक ने नोट किया कि कुछ औद्योगिक इकाईओं के खुलने के साथ, सभी कामगारों को वापस नहीं लिया जा रहा है, केवल एक छोटा प्रतिशत नौकरियों में अपनी जगह वापस पा रहा है और वो भी कम वेतन पर और लॉकडाउन अवधि के वेतन का भुगतान करने से इंकार पर। इस प्रकार के रोजगार से इंकार और वेतन–कटौती के लिए दबाव डालने का एकजुटता से सामना करना होगा। 20000 कर्मचारियों को छह महीने के लिए बिना वेतन के छुट्टी पर जाने का नोटिस देने का एयर इंडिया के अधिकारियों का हालिया निर्णय, जिसमें बिना वेतन के अनिवार्य (जबरन) छुट्टी का प्रावधान शामिल है, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। यह मौजूदा कानूनों का घोर उल्लंघन है।

बेरोजगार 14 करोड़ से अधिक हैं और यदि हम रोज कमाने वालों/ठेका/आकस्मिक को जोड़ते हैं, तो यह 24 करोड़ से अधिक हैं जो वर्तमान में आजीविका के बिना है। एमएसएमई स्वयं सूचित कर रहे हैं कि 30% से 35% इकाईयां अपनी गतिविधियों को शुरू करने की स्थिति में नहीं हो सकती हैं। बेरोजगारी दर अधिक है। आईएलओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 40 करोड़ से अधिक लोग गहरी गरीबी में धकेले जायेंगे। प्रख्यात वैज्ञानिकों और चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि कुपोषण बढ़ेगा, भूखमरी एक दैनिक वास्तविकता बन जायेगी, जिससे अवसाद का वास्तविक खतरा होगा और जिसके परिणामस्वरूप कामगारों में आत्महत्यायें होंगी। ये सभी मुद्दे कामगारों को नाराज कर रहे हैं।

*जारी पृष्ठ 3*

बैठक ने एक बार फिर केन्द्रीय श्रम संगठनों के रूख को दोहराया कि सरकार न केवल समय से महामारी को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में विफल रही है बल्कि चार कीमती महीने बर्बाद कर दिए हैं, लोगों विशेष रूप से प्रवासी कामगारों के लिए गंभीर दुख उत्पन्न करते हुए अल्प सूचना के साथ अनियोजित लॉकडाउन लगाया, स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार करने के लिए और अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को सुरक्षा उपकरण प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में विफल रही, यह न केवल लॉकडाउन अवधि के दौरान आवश्यक सेवायें प्रदान करने वाले रेलवे, सुरक्षा, बैंकों, बीमा, दूरसंचार, डाक और अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली अत्यधिक सेवाओं को मान्यता देने में विफल रही, बल्कि उनके द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का समाधान नहीं किया, यह इंसानों और समाज के लिए चिकित्सा आपातकाल के रूप में लेने के बजाय प्रशासनिक मुद्दे के रूप में कोविड 19 की समस्या से निपटने में डगमगाई है। इसने लाखों कामगारों, किसानों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को भारी कष्ट पहुंचाया है, जबकि, सरकार केवल कॉर्पोरेटों और बड़े व्यवसायियों के साथ खड़ी रही।

केन्द्रीय श्रम संगठनों ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश और थोक निजीकरण, 100 प्रतिशत तक मुख्य क्षेत्रों में एफडीआई का प्रवेश – भारतीय रेलवे, रक्षा, बंदरगाह एवं डॉक, कोयला, एयर इंडिया, बैंक, बीमा जिसमें अंतरिक्ष विज्ञान और परमाणु ऊर्जा आदि का निजीकरण शामिल है, के लिए अपने विरोध को दोहराया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा और अन्य वित्तीय क्षेत्रों को भी बड़े पैमाने पर निजीकरण के लिए लक्षित किया जा रहा है। देश के प्राकृतिक संसाधनों और व्यवसाय को हड़पने के लिए भारतीय और विदेशी ब्रांडों के कॉर्पोरेट्स के पक्ष में उपाय किए जा रहे हैं जबकि आत्म–निर्भर भारत का नारे को लज्जाहीनता से आगे बढ़ाया जा रहा है। 48 लाख केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का डीए स्थिर रखने और 68 लाख पेंशनरों का डीआर स्थिर रखने के निर्णय, जिसका असर राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी पड़ रहा है, को सरकारी कर्मचारियों और केन्द्रीय श्रम संगठनों के प्रबल विरोध के बावजूद वापस नहीं लिया गया है। न ही सभी गैर–आयकर दाताओं के लिए रू. 7500/– के नकद हस्तांतरण की मांग को स्वीकार किया गया है। सरकार लॉकडाउन अवधि के वेतन के संबंध में अपने स्वयं के आदेश को पाने में विफल रही है, छंटनी नहीं और वेतन में कटौती नहीं को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपने स्वयं के आदेश को लज्जाहीनता से वापस ले लिया गया है जब कुछ नियोक्ता इन आदेशों के विरूद्ध अदालत में चले गए।

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईओं के निजीकरण और बिक्री के साथ आगे बढ़ने के अपने हठी रवैये के साथ बनी हुई है, और अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विदेशी प्रवेश को खतरनाक रूप से उदार बना रही है जैसे रक्षा उत्पादन 49 से 74% प्रतिशत तक के साथ–साथ निजीकरण के लिए 41 आयुध कारखानों का कॉर्पोरेटीकरण; यह चरणों में भारतीय रेलवे के निजीकरण की अपनी परियोजना के साथ आगे बढ़ रही है, नवीनतम स्थिति भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे और मानवशक्ति का उपयोग करके विशाल लाभ कमाने के लिए निजी खिलाड़ियों की सुविधा के लिए अत्यधिक लाभकारी मार्गों में 151 रेल सेवाओं को निजीकरण करने का विनाशकारी निर्णय है। विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरियों के लिए स्वीकृत पदों के आत्मसमर्पण और नई नौकरियों के सृजन पर प्रतिबंध की नीति नौकरियों के लिए युवा उम्मीदवारों के अहित में बनी हुई है। इस सबसे ऊपर पिछले दो महीनों में 22 मौकों पर पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने लोगों को एक और बड़ा झटका दिया है।

ऐसी सरकार जिसको कामगारों और लोगों के अधिकारों और बुनियादी अस्तित्व–अधिकारों के प्रति कोई सम्मान और चिंता नहीं है, वह किसी भी सहयोग के लायक नहीं है। हम कामगारों/कर्मचारियों और श्रम संगठनों को एक दूसरे के साथ एकजुटता में रहने, सभी सावधानियां बरतते हुए बीमारी का एकजुटता से सामना करने, यूनियनीकरण, सामूहिक सौदेबाजी, सभ्य कार्य करने की स्थिति, वेतन और भविष्य की सुरक्षा आदि के लिए हर संभव प्रयास करने की जरूरत है।

इस सरकार ने कामगारों और लोगों की बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं के बारे में क्रूर असंवेदनशीलता प्रदर्शित की है। इसका समर्थन और सहयोग नहीं किया जा सकता।

इसलिए केन्द्रीय श्रम संगठनों और फैडरेशनों/एसोसिएशनों का संयुक्त मंच ने निरंतरता के साथ क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर सरकार की जन–विरोधी, कामगार–विरोधी नीतियों के विरूद्ध संघर्ष को आगे बढ़ाने का आह्वान किया है। यह निर्णय लिया गया कि;

*जारी पृष्ठ 4*

1. 9 अगस्त को – ''भारत छोड़ो दिवस'' को देशव्यापी सत्याग्रह/जेल भरो – या सभी कार्यस्थलों/औद्योगिक केन्द्रों/जिला मुख्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों आदि में जुझारू आंदोलन के किसी अन्य रूप के माध्यम से ''भारत बचाओ दिवस'' के रूप में मनाया जाना चाहिए।

2. 18 अगस्त 2020 को कोयला कामगारों की हड़ताल के दिन, सभी कार्यस्थलों पर और विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जुझारू एकजुटता कार्रवाई, जहां भी संभव हो हड़ताली कार्रवाई की संभावना तलाश की जानी चाहिए।

3. रक्षा क्षेत्र की यूनियनों/फैडरेशनों ने संयुक्त रूप से 99 प्रतिशत से अधिक कामगारों द्वारा अनुमोदित हड़ताल के लिए मतदान के आधार पर हड़ताल का नोटिस देने की योजना बनाई है। वे सितबंर 2020 के मध्य में कभी भी हड़ताल की कार्रवाई के लिए जा सकते हैं। केन्द्रीय श्रम संगठनों और फैडरेशनों के संयुक्त मंच ने रक्षा क्षेत्र की हड़ताल के साथ समन्वय करते हुए सरकार की नीतियों के खिलाफ देशव्यापी आम हड़ताल का विचार प्रकट किया और सभी संबद्धों से इस दिशा में तैयारी शुरू करने का आह्वान किया।

4. यह नोट किया गया कि योजना कामगारों की यूनियनों/फैडरेशनों (आंगनबाड़ी, आशा, मिड डे मिल आदि) ने संयुक्त रूप से 7 और 8 अगस्त 2020 को दो दिवसीय हड़ताल पर जाने का निर्णय किया है, जो 9 अगस्त 2020 को देशव्यापी सत्याग्रह/जेल भरो/आंदोलन के साथ मिलेगा। केन्द्रीय श्रम संगठनों और फैडरेशनों की संयुक्त बैठक ने सभी संबद्धों से योजना कामगारों की हड़ताली कार्रवाई के प्रति एकजुटता व्यक्त करने का आह्वान किया।

5. रेलवे क्षेत्र की यूनियनों/फैडरेशनों के साथ तालमेल में तथा स्वतंत्र रूप से भी रेलवे के निजीकरण पर सरकार के कदम के खिलाफ देशव्यापी अभियान जारी रखने का भी निर्णय लिया गया है। रेलवे फैडरेशनों ने सूचित किया कि वे उचित समय पर अपनी प्रतिक्रिया/कार्रवाई की योजना बना रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं।

6. यह सहमति हुई कि अभियान के रूप में भारत के राष्ट्रपति के लिए याचिका जो केन्द्रीय श्रम संगठनों के बीच प्रसारित है, को सुझाव प्राप्त करने का बाद अंतिम रूप दिया जायेगा और फिर इसे change.org अभियान के रूप में शुरू किया जायेगा। विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के कामगारों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए एक अन्य याचिका शुरू करने के लिए बैठक में एक और सुझाव लिया गया था। यह निर्णय भी लिया गया कि केन्द्रीय श्रम संगठनों का मंच 9 अगस्त के कार्यक्रम की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा के लिए एक बार फिर 27 जुलाई को बैठक करेगा ताकि इसे प्रभावी और दृश्यमान बनाया जा सके।

हम केन्द्रीय श्रम संगठनों की सभी प्रदेश इकाईओं का आह्वान करते हैं कि वे आंदोलन के अगले चरण के बारे में योजना बनाने के लिए क्षेत्रीय फैडरेशनों और एसोसिएशनों को आमंत्रित करते हुए अपनी बैठकें आयोजित करें, और इसे जिलों तथा उद्यम/उद्योग स्तर तक ले जायें।

**इंटक–एटक–एचएमएस–सीटू–एआईयूटीयूसी–टीयूसीसी–सेवा–एआईसीसीटीयू–एलपीएफ–यूटीयूसी**

**और क्षेत्रीय फैडरेशनें और एसोसिएशन**